

आज होगा इंडो-फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव

कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में होगा कार्यक्रम

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 11 मई. मप्र ने उद्योग, अधोसंरचना, नीति सुधार, लाइजस्टिक्स, स्क्रिल डेवलपमेंट और निवेश सुविधा के क्षेत्र में जिस तेज गति से कार्य किया है, उसने दुनिया की बड़ी कंपनियों का ध्यान राज्य की ओर आकर्षित किया है। फ्रांस की प्रतिष्ठित कंपनियों और उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की भोपाल में मौजूदगी इसी बढ़ते विश्वास का संकेत मानी जा रही है।



भोपाल में 12 मई को होने जा रहे इंडो-फ्रेंच इन्वेस्टमेंट कॉन्क्लेव ऐसे समय में हो रहा है, जब

मध्यप्रदेश वैश्विक निवेश मानचित्र पर लगातार मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। कुशाभाऊ अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में यह आयोजन केवल एक निवेश बैठक नहीं, बल्कि उस बदलती औद्योगिक सोच और वैश्विक संवाद का विस्तार है। इसमें मध्यप्रदेश अब निवेश प्राप्त करने वाले राज्य की भूमिका से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक साझेदारियों का सक्रिय केंद्र बन रहा है। इंडो-

फ्रेंच चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मप्र शासन के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में फ्रांस के राजदूत, फ्रांसीसी उद्योग जगत के प्रतिनिधि, वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी, मप्र शासन के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और प्रदेश के उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे। कॉन्क्लेव से मध्यप्रदेश और फ्रांस के बीच दीर्घकालिक औद्योगिक, तकनीकी और संस्थागत साझेदारी होगी। इससे

कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में 12 मई को आयोजित होने वाले मुख्य सत्र में मप्र की औद्योगिक नीतियों, निवेश प्रोत्साहन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश सुविधा सिस्टम पर विस्तृत प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव कार्यक्रम के मुख्य सत्र को संबोधित करेंगे प्रदेश के लगभग 60 से 80 उद्योग प्रतिनिधियों की भागीदारी भी कार्यक्रम में प्रस्तावित है। इनके और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच बी-2-बी और बी-2-जी बैठकें आयोजित होंगी, जिनमें संभावित निवेश, संयुक्त उपक्रम, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा होगी।

राज्य सरकार फ्रांसीसी कंपनियों को मप्र के औद्योगिक वातावरण, निवेश संभावनाओं, नीति समर्थन और तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक इको-सिस्टम से अवगत कराएगी। कार्यक्रम में एग्री एवं फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल

एवं ईवी, कंज्यूमर गुड्स एवं रिटेल, डिफेंस एवं एविएशन, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, फार्मा एवं मेडिकल डिवाइसेस, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल, पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा।

फर्जी एससी प्रमाण पत्र के मामले में कार्रवाई की मांग

विशेष संवाददाता
भोपाल, 11 मई. मध्यप्रदेश में फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के मामलों को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने सतना जिले में कथित रूप से फर्जी एससी प्रमाण पत्र जारी करने के मामले में तत्कालीन एसडीएम के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की है। मध्यप्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) और सामान्य प्रशासन विभाग को शिकायत सौंपकर पूर्व एसडीएम



राजेश शाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वंदना बागरी के नाम से जारी जाति प्रमाण पत्र वर्ष 2021 में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए जाने के कारण निरस्त कर दिया गया था।

एक नजर में फॉयरिंग मामले में निष्पक्ष जांच की मांग

आगरमालवा. जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र के ग्राम मगीशपुर में गत पांच मई को हुई फायरिंग की घटना में नामजद आरोपियों के परिजनों ने आज पुलिस थाने पहुंचकर निष्पक्ष जांच की मांग की। ग्रामीणों ने सुसनेर थाना प्रभारी अक्षयसिंह वैस को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाया कि मामले में कुछ निरीक्षकों को फर्जी तरीके से आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने इस मामले में चार लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें ईश्वरसिंह और हेमराज भी शामिल हैं। आरोपियों के परिजनों का कहना है कि दोनों का घटना से कोई संबंध नहीं है। मांगूसिंह ने पुलिस प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि किसी प्रकार के दबाव में आकर हेमराज लोगों को आरोपी नहीं बनाया जाना चाहिए।

21 किलो गांजे के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

मैहर. जिले की पुलिस ने 21 किलोग्राम गांजा बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सुओं के अनुसार रविवार देर रात में रामनगर-भदनापुर मार्ग पर कार से गांजे की खेप ले जा रहे अनिल द्विवेदी (37) और विष्णुकांत पांडे (27) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 21 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।



रतलाम में पारा 45 डिग्री मध्यप्रदेश में मौसम कर रहा है डबल अटैक

उमस के साथ गर्मी को भी झेलेंगे लोग मध्यप्रदेश में गर्मी का सितम

भोपाल, 11 मई. प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों दो अलग तस्वीरें दिखा रहा है। पूर्वी और दक्षिणी जिलों में आंधी-बारिश का दौर जारी है, जबकि मालवा और मध्य हिस्सों में भीषण गर्मी लोगों को झुलसा रही है। मौसम विभाग के अनुसार दो टर्फ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सक्रिय होने के कारण अगले 24 घंटे तक कई जिलों में तेज हवाएं, गरज-चमक और हल्की बारिश का असर बना रहेगा। वहीं दूसरी तरफ तापमान लगातार बढ़ने से कई शहरों में लू जैसे हालात बनने लगे

इंदौर में 43 डिग्री पहुंचा पारा इंदौर में आज गर्मी ने इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और तापमान 43.2 डिग्री तक पहुंच गया। आज दिन का पारा सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा। शहर में 10 से लेकर 18 किलोमीटर प्रति घंटे के रफतार से लू चली। रात का तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 24.7 दर्ज किया गया। शहर में गर्मी का कहर बढ़ता जा रहा है और आज शाम 6 बजे पारा 40.6 डिग्री दर्ज हुआ। दिन में तापमान ने लू लगने जैसी गर्म हवाओं के थोड़े लगे रहे थे। दिन में तापमान ने इस साल को रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 43.2 डिग्री पाठ पहुंचा था। इसके पहले इस साल अप्रैल के शुरू में पारा 43 डिग्री तक पहुंचा था।

पेज एक का शेष

सिंधिया के 'आर्थिक और ढांचागत मॉडल' की भूमिका

इसके तहत राज्य के ग्रामीण और जनजातीय बहुल इलाकों में शिक्षा और बुनियादी ढांचे के इस सीधे जुड़ाव ने ग्रामीण असम में भाजपा के पक्ष में एक मजबूत 'साइलेंट वोट' वर्ग तैयार किया। इसके अलावा संचार मंत्री के हैसियत से सिंधिया की 'टेलीकॉम सैचुरेशन' नीति असम के ऊपरी और निचले हिस्सों के चाय बागानों तथा सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में गेमचेंजर साबित हुई। पूर्वोत्तर में हजारों टावरों के माध्यम से निर्बाध

नेटवर्क पहुंचाना केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि इसने सरकारी योजनाओं के सीधे लाभ को पारदर्शी बनाया। भ्रष्टाचार पर इस डिजिटल प्रहार ने सरकार के प्रति जनता के विश्वास को और गहरा किया और साथ ही तीव्र प्रशासनिक निगरानी ने असम के शहरी और शिक्षित युवाओं की आकांक्षाओं को पंख दिए। जानकार बता रहे हैं कि सिंधिया के सार्थक प्रयास के कारण ही स्थानीय बांस शिल्पकारों, हैंडलूम बुनकरों और

मूल्यवान अगरवुड के उत्पादकों को विश्वस्तरीय निर्यात पोर्टल्स से जोड़कर असमिया अस्मिता और स्थानीय अर्थव्यवस्था को ताकत मिली। साथ ही इसने असमिया संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक पहचान 'हाई-टेक असम' की छवि और गौरव को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के 'राष्ट्रवाद' के नैरेटिव से पूरी तरह जोड़ दिया। जिसके कारण भाजपाई रणनीतिकारों को बड़ी सफलता मिली।

प्रदेश में बंद आरटीओ के चेक पोस्ट पुनः प्रारंभ करने पर रोक

हाईकोर्ट के उक्त आदेश के खिलाफ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कंग्रिडाइज्ड कंपनी व अन्य की तरफ से हाईकोर्ट में रिक्वायिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता राहुल दिवाकर ने हाईकोर्ट को बताया गया कि केन्द्र सरकार के दिशा-निदेशानुसार प्रदेश में चेकपोस्ट बंद किये गये थे। देश में मध्य प्रदेश सहित सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं, जिसमें चेक पोस्ट संचालित हो रहे। केन्द्र सरकार के निर्देशानुसार अन्य प्रदेश पहले ही चेक पोस्ट बंद कर दिये हैं।

विस्थापित चर्चा

सरकार आदिवासी जमीनों का अधिग्रहण बेहद कम कीमत पर कर रही : पटवारी

केन-बेतवा विस्थापन पर कांग्रेस करेगी आंदोलन

विशेष संवाददाता
भोपाल, 11 मई. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केन-बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से प्रभावित आदिवासी परिवारों और किसानों की समस्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को पन्ना जिले के विश्रामगंज और बालपुर गांवों के दौरे के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि प्रभावित परिवारों को न तो उचित मुआवजा दिया जा रहा है और न ही सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था की गई है।



प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात के बाद पटवारी ने कहा कि कांग्रेस उनके अधिकार, सम्मान और न्याय की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस नेता

राहुल गांधी का संदेश लेकर प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हैं, जो आदिवासियों, किसानों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। पटवारी ने

किसानों की स्थिति पर चिंता जताते हुए पटवारी ने कहा कि प्रदेश के गेहूं उत्पादकों को 2,000 से 2,300 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर उपज बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रभावित परिवारों को न्यायपूर्ण मुआवजा और सम्मानजनक पुनर्वास नहीं मिला तो कांग्रेस प्रदेशव्यापी आंदोलन, चक्काजाम और सड़क अवरोध प्रदर्शन शुरू करेगी।

अधिकारियों से विस्थापित परिवारों की संख्या, वितरित मुआवजे और पुनर्वास योजनाओं की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने मांग की कि परिवारों में रहने वाले व्यक्तियों को अलग परिवार मानकर मुआवजा और पुनर्वास का लाभ दिया जाए। मुआवजा पैकेज पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आवास के लिए मात्र एक

लाख रुपये दे रही है, जबकि क्षेत्र में जमीन की कीमतें इतनी अधिक हैं कि इस राशि में छोटा भूखंड भी खरीदना संभव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी जमीनों का अधिग्रहण बेहद कम कीमत पर कर रही है, जबकि भूमि अधिग्रहण नीति में चार गुना मुआवजे का वादा किया गया था।

टैलेंट हंट का फाइनल इंटरव्यू आज से

भोपाल में आयोजित किए जाएंगे इंटरव्यू

विशेष संवाददाता
भोपाल, 11 मई. मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग द्वारा आयोजित 'टैलेंट हंट प्रोग्राम' के तहत चयनित प्रतिभागियों के फाइनल इंटरव्यू 12 और 13 मई को प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय, भोपाल में आयोजित किए जाएंगे। पार्टी इस पहल के जरिए प्रदेशभर में अपने मीडिया और संचार तंत्र को मजबूत करने की तैयारी में जुटी है। मध्यप्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने बताया कि दो दिवसीय प्रक्रिया के



इनमें जौनल कोऑर्डिनेटर अनिल यादव, स्टेट कोऑर्डिनेटर अखिलेश प्रताप सिंह, मीडिया विभाग के कोऑर्डिनेटर अर्चित सिंह तथा टेकिनिकल कोऑर्डिनेटर अर्श खान शामिल हैं। नायक ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य मीडिया और संचार क्षेत्र में युवा, प्रतिभाशाली और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नेतृत्व तैयार करना है, ताकि पार्टी की विचारधारा और संदेश को प्रभावी ढंग से आमजन तक पहुंचाया जा सके।

भ्रष्टाचार को लेकर पटवारी ने भाजपा को घेरा बिगड़ती कानून व्यवस्था, प्रशासनिक विफलताओं पर लगाए आरोप

विशेष संवाददाता
भोपाल, 11 मई. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सतना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा विधायकों, मंत्रियों और उनके समर्थकों को मनमाना करने तथा अधिकारियों को डराने-धमकाने की खुली छूट दे दी गई है। उन्होंने शिवपुरी के भाजपा विधायक प्रीतम लोधी से जुड़े

हालिया पनसीआरबी रिपोर्ट का हवाला देते हुए पटवारी ने दावा किया कि देश में दर्ज कुल अपराधों में 32 प्रतिशत मामले मध्यप्रदेश से जुड़े हैं। उन्होंने महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति और बुजुर्गों के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए सरकार से तत्काल कठोर कार्रवाई और जवाबदेही तय करने की मांग की।

हालिया विवाद का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारी अधिकारियों के साथ धमकी और अभद्र भाषा का प्रयोग सत्ता पक्ष की कार्यशैली को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश अब 'जंगलराज' का पर्याय बन चुका है और प्रदेश की स्थिति अब बिहार तथा उत्तरप्रदेश जैसी दिखाई देने लगी है। पटवारी के अनुसार अपराधियों में कानून का भय समाप्त हो चुका है जबकि सरकार

मूकदर्शक बनी हुई है। कांग्रेस नेता ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप देने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में शायद ही कोई ऐसा सरकारी कार्यालय बचा हो जहां बिना रिश्तेदार के आम जनता का काम होता हो। उन्होंने सतना और रीवा संभाग के पत्रकारों को चुनौती देते हुए कहा कि यदि कोई ऐसा कार्यालय मिले जहां भ्रष्टाचार न हो तो कांग्रेस उसका सार्वजनिक सम्मान करेगी।